

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

(150)

फॉर्माक:- प.5(उनविवि/३/१९

जयपुर दिनांक 2 NOV 2007

परिपत्र

विषय:- फॉर्मि.पर यसी हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन छेत्र
सुधारन्त पैरालीटर्स में शिथितन चाहत।

इस विभाग द्वारा उपर्युक्त समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08.09.07 में दिये
निटेशन के बेन्दु कं. 1(3) में निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

जन कॉलोनियों में 22.12.99 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो
चुका है उनमें निर्मान कान साहब निजती एवं पानी के बिल अतिरिक्त निम्न अन्य
दस्तावेजात वा इस श्रेणी में, ज्ञानलित होंगे वशर्ते कि ऐसे दस्तावेजात में
संविधित व्यापार के निवास संधान का प्रता उसी जगह का अंकित हो, जहां का
वह पट्टा बहता है। जल्द ऐसे स्थिति में साहब के रूप में निम्नलिखित
दस्तावेज माल्य होंगे :-

1. निजली एवं पानी के बिल
2. नासपोर्ट
3. हाईविंग लाईसेन्स
4. आपार यहान पत्र (पेनकार्ड)
5. सार्वजनिक हेत्र के बैंक/ डाकघर/ किसान पास युक

(देनका 22.12.99 पा उससे पूर्व खोला गया थां।)

6. रमाती दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि
7. पेशन दस्तावेज जैसा कि भूतपूर्व सेनिक पेशन, भूतपूर्व सेनिक, विश्वा
/पेशन अदायगी, उत्तरा /आक्रित प्रभाण-पत्र/ वृद्धावस्था पेशन
आदेश/ वेधवा पंगः अ देश
8. रातंडा रीनांगी प्रणाली-पत्र

उवं परिपत्र में अन्य शर्तें यथावत रहेगी। यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समस्त शर्तें 70 से 75 प्रतिशत तक आवासीय क्षेत्रफल वाली योजनाओं के नियमन हेतु ब व्यकारी है। इससे कम अनुपात की अवस्था में विभागीय परिपत्र दिनांक 1.01.02 के अनुरूप ही नियमन की कार्यवाही हु निश्चित की जाएगी है।

(परविन्दर सिंह)
ग्रमुख शासन सचिव

प्रतिशिखा:-

1. निजी साधेव, मा. मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यसभी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य साधेव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, ग्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन भविव, स्थानीय शासन विभाग, जयपुर।
6. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. देश क, रथानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. घोषणा, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. अधिकारी पत्राधारी।

प्रमोद
शासन उप सचिव-प्राधिकरण